

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर
रीठासीन अधिकारी :- रिया केजरीवाल, आई.ए.एस.
राजस्व अपील सं०- 19/2015



सोनीदेवी बैवा भैराराम नायक निवासी ग्राम बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर

—:बनाम:—

अपीलान्ट

1. अवार्ड अवाप्ति अधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत प्रथम, बीकानेर सड़क बाईपास रोड।
2. राजस्थान सरकार

...रेस्पोंडेंटान

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति अभिभाषक:-

1. श्री विजय कुमार पारीक, अपीलान्ट।
2. परोकारराज, राज्य की ओर से।

—:निर्णय:—

दिनांक-17/01/2020

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन न्यायालय तहसीलदार बीकानेर नामान्तरण संख्या 35 दिनांक 03.04.2000 के विरुद्ध मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अपील प्रकरण के आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि चक 9 बीएसएम के मु.न.177/20 के किला न.9,11,12,13,18,19,23 व 24 की 3 बीघा 5 बिस्वा एवम मु.न.177/21 के किला न.3,4,8 की 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि हेतु अपीलान्ट को सुने बिना व बिना अवाप्त किये तथा बिना मुआवजे दिये। रेस्पोंडेंट न. 2 द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 अवार्ड अवाप्ति अधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत प्रथम बीकानेर के नाम दर्ज कर दी गयी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 8.6.15 को Subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को जरिये समन तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 8.6.16 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की 9 बीएसएम पटवार मण्डल उदासर का इंतकाल नम्बर 35 दिनांक 3.4.2000 अवार्ड अवाप्ति अधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत प्रथम बीकानेर के पत्रांक 612 दिनांक 24.12.97 व तहसीलदार बीकानेर के पत्रांक 94 दिनांक 12.1.98 की पालना में सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क बाईपास के नाम इंतकाल दर्ज किया गया है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

आदेश के विरुद्ध अपील इस न्यायालय में दायर नहीं की जा सकती। अतः अपील खारिज योग्य है। जिस पर अपील बहस हेतु नियत की गयी।

बहस सुनी गयी। प्रकरण में अपीलान्त के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए नामान्तरण को खारिज कर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड कर पुनः सुनने हेतु निवेदन किया। राज पैरोकार ने राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने का निवेदन किया और साथ ही कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेश के विरुद्ध अपील इस न्यायालय में दायर नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

हमने अपील व बहस तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। मियाद के बिंदु पर अपीलान्त का धारा 5 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का विश्वास किया जाकर न्यायहित में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी का यह तथ्य कि उक्त भूमि का इंतकाल करते समय बेचानकर्ता को सुनना जरूरी था खारिज योग्य है। रेस्पोंडेन्ट के जवाब अनुसार उक्त भूमि की अवाप्ति आदेश दिनांक 24.12.97 (अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त प्रथम पत्राक-612) व तहसीलदार के पत्राक-94 दिनांक 12.1.98 की पालना में करी गयी। जो न्यायालय की दृष्टि से सही होना पाया गया। अवाप्ति की प्रक्रिया में अपीलान्त को नोटिस द्वारा सूचित करवाया गया। अगर अपीलान्त अवाप्ति की प्रक्रिया पर प्रश्न उठाता है तो वह इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। वह सक्षम न्यायालय में इसकी अपील करने को स्वतंत्र है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17-1-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



Me
(रिया केजरीवाल)
आईएस
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर राजस्थान

